PAGE No - 27 - 21/10/14
DAINIK JAGRAN



# बैकफुट पर चीनी मिलें, पेराई को राजी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : गन्ना पेराई सत्र शुरू करने को जारी कवायद में सोमवार को आस बनती नजर आई। निजी चीनी मिलों में मरम्मत कार्य अगले 24 घंटे में शुरू कराने के लिए सशर्त सहमति बन गई है। मंगलवार को आगे की वार्ता होगी।

उप्र शुगर मिल्स एसोसिएशन (एस्मा) के सूत्रों ने कहा कि सरकार ने मिलों की कई प्रमुख मांगें स्वीकार कर लेने के संकेत दिए हैं। इसमें बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान करने के लिए मिलों को तीन रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त मदद देने के अलावा विभिन्न मिल प्रबंधकों के खिलाफ दर्ज रिपोर्ट और वसूली प्रमाणपत्र वापस लेने को सरकार राजी है। मिलों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए कई बिंदुओं पर भी प्राथमिक तौर से एक राय बनी है। सोमवार देर शाम मिल मालिकों की ओर से जारी बयान में पेराई सत्र आरंभ

◆ बकाया गन्ना मूल्य पर तीन रुपये प्रति क्विंटल की अतिरिक्त रियायत

करने का फैसला किया गया है। इसके लिए रखरखाव व मरम्मत जैसे कार्य अगले 24 घंटों में सभी मिलों में शुरू हो जाएगा जिसे एक पखवाड़े में निपटाने का प्रयास होगा।

**लिंकेज फार्मूले पर अभी चर्चा नहीं :** गन्ना समर्थन मूल्य तय करने के लिए मंगलवार को प्रस्तावित बैठक में मिल मालिक भाग लेंगे। अब तक निजी मिलों द्वारा विभागीय गतिविधियों का बहिष्कार किया जा रहा था। सूत्रों का कहना है कि हाई कोर्ट के सख्त रुख के बाद सरकार और मिलों ने समझौते की राह निकाली है।

## 350 रुपये से कम गन्ना मूल्य मंजूर नहीं

◆ मूल्य निर्धारण समिति की बैठक आज

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : गन्ना समर्थन मूल्य तय करने के लिए हाईपावर कमेटी की बैठक मंगलवार को होगी, लेकिन मूल्य निर्धारण को लेकर दबाव की सियासत तेज है। किसान जहां 350 रुपये प्रति क्विंटल से कम गन्ना मूल्य स्वीकारने को तैयार नहीं है वहीं मिल मालिकान इसके लिए राजी नहीं।

सोमवार को प्रशासनिक अमला दिन भर गन्ना मूल्य आकलन को जोड़तोड़ में लगा रहा। सूत्रों के मुताबिक गन्ना उत्पादन लागत का आकलन गत वर्ष से अधिक होने के कारण सरकार की दुविधा बढ़ी है। लगातार दूसरे वर्ष भी गन्ना का दाम नहीं बढ़ा तो सरकार के लिए किसान हितैषी छवि को बचाकर रखना मुश्किल होगा। उधर, चीनी मिल मालिकान वित्तीय संकट से निपटने की परेशानी में उलझे हैं। उप्र शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि आर्थिक कारण से मिलें बड़ी संख्या में श्रमिकों की छंटनी करने को मजबूर हैं। सोमवार को भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विजयपाल तोमर के नेतृत्व में गन्ना आयुक्त सुभाष चंद शर्मा को सौंपे ज्ञापन में गन्ना मूल्य 350 रुपये से कम न किए जाने की मांग की गई। तोमर का कहना था कि बकाया गन्ना मूल्य की ब्याज समेत अदायगी जल्द कराने के साथ खांडसारी उद्योग को भी प्रोत्साहित करने की नीतियां बनें।

21/10/14